

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 01 ^{अगस्त} जुलाई, 2017

विषय:- जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर में बहुउद्देशीय कीड़ाहॉल के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-625/भग0बहु0हॉ0हरि0पत्रा0/2014-15, दिनांक 20 जुलाई, 2017 के क्रम में शासनादेश संख्या-13/VI-2/2015-22(7)/2014, दिनांक 06 जनवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या-31/VI/2016-22(7)/2014, दिनांक 16 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर में बहुउद्देशीय कीड़ाहॉल के निर्माण कार्य शासनादेश दिनांक 06 जनवरी, 2015 के द्वारा अवमुक्त धनराशि ₹ 2.81 लाख के पश्चात् विभागीय समिति के बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 30 सितम्बर, 2015 के क्रम में द्वितीय चरण हेतु संशोधित कार्य हेतु प्राप्त आगणन का टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 116.14 लाख (सिविल निर्माण कार्य हेतु ₹103.98 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्य हेतु ₹12.16 लाख) मात्र की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किस्त के रूप में ₹ 50.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त अवशेष बची धनराशि ₹ 66.14 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में द्वितीय अवशेष अन्तिम किस्त के रूप में ₹ 66.14 लाख (छियासठ लाख चौदह हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-318/XXVII(1)/2014 दिनांक 18 मार्च, 2014 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0-474/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए तथा विलम्ब या अन्य किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
7. अधिप्राप्ति कार्यो हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधित नियमावली, 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
8. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।
9. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।
10. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-03 इण्डोर हॉल/हॉस्टल का निर्माण-24- वृहत निर्माण कार्य के मानक मद के पक्ष के नामें डाला जायेगा।
11. यह स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत की जा रही है।

संलग्नक :- अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-SI708300021, दिनांक : 01 जुलाई, 2017

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव (प्रभारी)।

पृष्ठांकन संख्या— 565 /VI/2017-22(7/2014, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० खेल मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साइबर कोषागार, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
7. जिला कीडाधिकारी, हरिद्वार।
8. महाप्रबन्धक (गढ०), निर्माण विंग, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
9. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, ऋषिकेश।
10. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य मोहन नौटियाल)

अपर सचिव।